



भारतीय महिलाओं की उन्नति : डॉ. अम्बेडकर का योगदान

माधवी राजहंस

प्रस्तावना :

भारतरत्न डॉ. 'भीमरावराजजी अम्बेडकर' ग्यारह भाषाओं के धुरन्धर विद्वान, समाजशास्त्र के प्रकाण्ड पंडित, कुशलराजनीतिज्ञ, समस्तधर्मों एवं दर्शनों के ज्ञाता, आधुनिक भारत के निर्माता एवं दलितों के मुक्तिदाता, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानूनमंत्री, संविधान विधाता, मानवतासमता एवं स्वतंत्रता के उपासक, ज्येष्ठ शिक्षणतज्ञ, हिंदुकोड बिल के समर्थक एवं नारी जगत के उद्धारक के रूप में हमारे सामने आते हैं।

प्राचीनकाल से ही संभवतः बारहवीं, तेरहवीं और उन्नीसवीं सदी के मध्य तक हम देखते हैं कि नारी जाति की हमेशा दुर्गति ही सामने आयी है। जिस तरह हजारों वर्ष की परम्परा में शूद्रों एवं अछूतों की ओर किसीने ध्यान नहीं दिया, ठीक उसी तरह एक और वर्ग भी हमेशा दुर्लक्षित रहा, वह है सभी वर्गों की स्त्रियाँ। हाँ, कुछ कर्तृत्ववान महिलाओं के नाम भी सामने आते हैं, किंतु संख्या बहुत ही कम है। भारतीय प्राचीन धर्मग्रंथ मनुस्मृति के अनुसार बाल-विवाह, सती-प्रथा की बली चढ़नेवाली स्त्री आज देश की प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति बन सकती हैं। हर एक क्षेत्र में स्त्रीको ५० प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। इसके पीछे डॉ. भीमराव अम्बेडकर का संविधान है।



बाबासाहब केवल दलितों के मसीहानहीं थे बल्कि किसानों, मजदूरों, पिछड़ों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के हित में उन्होंने बड़ा काम किया है। संविधान में नारीको समान अधिकार व अछूतों के हित का विशेष ध्यान रखते हुए हजारों साल पुरानी परंपराको निरस्त कर दिया गया है।

आज तक भारतीय महिलाओं के कई उद्धारक सामने आए हैं, किंतु उनका सही मार्गदर्शक एवं मुक्तिदाता केवल एक ही है, 'डॉ. भीमराव अम्बेडकर।' भारत का आद्य धर्मशास्त्र याने कानून की किताब माने जानेवाले 'मनुस्मृति' ग्रंथ ने शूद्रों, दलितों एवं स्त्रियों के अधिकार पूर्णतः छीन लिए थे। उनके साथ पशुओं- से भी ओछा व्यवहार किया था। अतः इस देश की अमानवीय सामाजिक व्यवस्था में 'स्त्री' प्रत्येक स्थान पर नकारा गयी है। मनुस्मृति ने स्त्री-दास्यता का हमेशा समर्थन किया है, जिसका प्रभाव आज भी जनमानस पर दिखाई देता है। आज के वैज्ञानिक युग में भी स्त्रियों पर अमानुष अन्याय, अत्याचार होते दिखाई देते हैं। अतः स्पष्ट है कि किसी भी सुधारवादियों को यह ग्रंथ कदापि मान्य होनेवाला नहीं था। संक्षेप में महाडजलसत्याग्रह के समय २४ दिसंबर १९२७ को अम्बेडकरने 'मनुस्मृति दहन' का प्रतीकात्मक कार्य करके स्त्रीस्वतंत्रता का पहला कदम उठाया था, ऐसा कहेंगे तो भी गलत नहीं होगा। भारतीय महिलाओं को स्वातंत्र्य देनेवाले महामानव डॉ. भीमरावको कोटी कोटी प्रणाम....।

स्त्रीवर्ग की प्रगति में डॉ. साहब का अटूट विश्वास था। उन्होंने हमेशा स्त्री शिक्षा का पुरस्कार किया। देश की समस्याओं को सुलझाने में तथा सामाजिक बुराइयों को दूर करने में स्त्रीवर्ग अधिक सहायता कर सकती है, ऐसी उनकी निष्ठा थी। वे कहते थे, 'किसी समाज की प्रगति स्त्री-वर्ग की उन्नति से ही नापी जा सकती है।' अतः अम्बेडकर के कई आंदोलनों में स्त्रियों का प्रत्यक्ष सहभाग भी महत्वपूर्ण रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र आज भी पुरुष प्रधान है, तो उस समय सामान्य स्त्रीको घर से बाहर कदम रखना कितना मुश्किल रहा होगा? ऐसी स्थिति में दलित, शोषित वर्ग की स्त्रीको घर से बाहर निकाल के प्रत्यक्ष आंदोलन में सक्रिय कराना यह बात अभूतपूर्व थी। आज भी कई स्त्रीसंगठनों में स्त्रियों की उपस्थिति न्यूनतम होती है, किंतु बाबासाहब के आंदोलनों में स्त्रीसंख्या लक्षणीय थी। अतः उन्हें आंदोलनों में प्रत्यक्ष स्त्री-सहभाग के जनक भी कहा जाता है।

किसी भी आंदोलनको तात्विक अधिष्ठान प्राप्त होना जरूरी होता है। अम्बेडकरने स्त्री के गुलामीका अंत करने के लिए आवश्यक तत्वज्ञान अपने लेखनी से 'स्त्री-मुक्ती आंदोलन' को दिया है। स्त्री-पुरुषसमानता प्रस्थापित कराने के लिए डॉ. अम्बेडकरने महत्वपूर्ण अस्त्रका उपयोग किया, वह है कानून। उनके मन में स्त्री और शूद्रजनता पर जातिव्यवस्थाने किया हुआ अन्याय, अत्याचार के प्रति अत्यंत चोढ़ थी। महिलाओं के हित में हिंदूकोड बिल पास कराने में उन्हें एंडी-चोटी कापसीना एक करना पड़ा किंतुकुछ कट्टर सनातनी रुढ़िवादियों की वजह से वह बिल पूरी तरह पास न हो सका। इसके लिए उन्होंने स्वयं के मंत्रीपदका भी त्याग किया था। अतः वही बिल पाँचवर्ष पश्चात कुछ परिवर्तन के बाद पास किया गया। उसका जो भी अंश पास हो सका, उसका लाभ आज महिलाओं को मिल रहा है। संपत्ति में बराबरीका संवैधानिक अधिकार उन्हें मिल चुका है। सन १९५२ के बाद केंद्र सरकारने उसी बिल से ४ स्वतंत्र कानून बनाए - दि हिंदू मरैज अक्ट (१९५५), दि हिंदू सक्सेशन अक्ट (१९५६), दि हिंदू मायनॉरिटी अंड गार्डीयनशिप अक्ट (१९५६), दि हिंदू अडॉप्शन अंड मेन्टेनेन्स अक्ट (१९५६) आदि। अतः अम्बेडकर के इस कार्य के लिए भारतका स्त्रीवर्ग उनका हमेशा ऋणी रहेगा।

डॉ. अम्बेडकरने परंपरागत विधिशास्त्र में खड़ी हुई स्त्रीको संविधानद्वारा प्रदत्त समान अधिकारों से बंधनमुक्त किया है। संविधान में स्त्री-पुरुष, धर्म जाति और जन्म के आधार पर किसी भी प्रकारका भेदभाव नहीं किया है। वे हमेशा यही चाहते थे कि अब स्त्रीवर्ग सामाजिक तथा राजनैतिक क्षेत्रों के सुधार में पीछे न रहे और उन्हें खुशी भी थी कि स्वतंत्र भारत में स्त्रीवर्ग ने काफी प्रगति की है। उन्हीं के प्रयत्नों से बम्बई विधानसभा में महिलाओं को प्रसूति के बाद तीन महिने के अवकाशका जो अधिकार मिला था, उसे बाद में देश भर में मान लिया गया। स्त्रियों की शैक्षिक प्रगति का आलेख दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है। आज भारत में सभी क्षेत्रों में आय. ए. एस., बकिल, न्यायाधीश, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, बिज़नेस मनेजमेंट अधिकारी, इंजिन ड्रायव्हर्स, पायलट्स से लेकर बस ड्रायव्हर्स, अटो रिक्शा ड्रायव्हर्स, रेलवेहम्माल तक का कार्य स्त्रियाँ कर रही हैं। विविध पुरुष प्रधान पदों पर भी उसने अपना कर्तृत्व सिद्ध किया है। तात्पर्य ज्यादा से ज्यादा शिक्षक, प्राध्यापक, एवं नर्स तक स्त्रियाँ काम कर सकती हैं। ऐसा सोचनेवालों को स्त्रियों ने अच्छा सबक सिखाया है।

संक्षेप में पारंपारिक दृष्टिकोण विशेषतः महिलायें सिर्फ घर-गृहस्थी, बच्चों की परवरिश, रसोई, सफाई आदि काम करे, ऐसा सोचनेवाले थे। स्त्रीको नियंत्रित रखनेवालों के सामने स्त्री आज एक आह्वान बनकर खड़ी हैं, तो इसके पीछे डॉ. अम्बेडकरका विधिशास्त्र है।